उत्पादन लागत गिरेगी, आय बढ़ेगी : वित्त मंत्री

सीतारमण ने एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर की पहली खेप को हरी झंडी दी

जैव-कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी दरों में

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैव-कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी दरों में कटौती से देश के किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा और इससे वे और अधिक सशक्त बनेंगे.

वित्त मंत्री बुधवार को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मेथागल गांव में एग्रो प्रोसेसिंग के लिए फार्मर्स ट्रेनिंग कम कॉमन फैसिलिटी सेंटर से उत्पादों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर बोल रही थीं.

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जीएसटी प्रणाली को पहले से अधिक आसान और जनहितैषी बनाया गया है. उन्होंने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन ही 'नेक्स्ट जेन जीएसटी' को लागू किया गया है, जिससे व्यापार और किसानों दोनों को राहत मिलेगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ट्रैक्टर, सौर ऊर्जा चालित उपकरणों और किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य कृषि मशीनरी पर जीएसटी दरों में कमी की है. उन्होंने कहा, जैव-कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी घटाने से किसानों की उत्पादन लागत कम होगी और उनकी आय में वृद्धि होगी. उन्होंने कोप्पल जिले की कृषि विविधता की सराहना करते हुए कहा कि यह जिला उत्तर कर्नाटक का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जो राज्य के कुल धान उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत योगदान देता है.

> सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को जन-आंदोलन बनाया है और मेथागल गांव में शुरू किया गया नया सेंटर इस विचार का उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने बताया कि कर्नाटक में पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 43 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है. कार्यक्रम के बाद वित्त मंत्री ने एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों के बारे में जानकारी ली.

पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में सहयोग करेगा भारत सऊदी अरब

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर. भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने तथा रसायन एवं पेट्रो रसायन क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों को तलाशने पर गहन चर्चा की है.

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज उप मंत्री इंजीनियर खलील बिन इब्राहिम बिन सलामाह के नेतृत्व में भारत के दौरे पर आये वहां के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुयी इस बैठक में भारत का नेतृत्व रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग की सचिव सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा ने किया. दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सालाना करीब 4.5 अरब डॉलर का कारोबार होता है.

वंदे भारत 4.0 बनेगी विश्वस्तरीय ट्रेन : वैष्णव

रेल मंत्री बोले– हर तकनीकी और सुविधा में होगा वैश्विक मानक

वंदे भारत 4.0 और अमृत भारत 4.0 अगले 18 महीनों में लॉन्च होंगी

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर. भारत रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. केंद्र सरकार ने अगले 18 महीनों में वंदे भारत 4.0 और अमृत भारत 4.0 ट्रेनों को लॉन्च करने का लक्ष्य तय किया है. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को 16वें इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्ज़िबिशन 2025 के उद्घाटन अवसर पर यह जानकारी दी.

वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत 4.0 ट्रेन पूरी तरह नई तकनीक और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस होगी. उन्होंने कहा, हमें वंदे भारत सेवा को पुनर्परिभाषित करना होगा और ऐसी तकनीक लानी होगी जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरी उतरे. इस नई ट्रेन में बेहतर टॉयलेट्स, उन्नत सीटिंग अरेंजमेंट और कोच के बेहतर निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. रेल मंत्री ने बताया कि वर्तमान में चल रही वंदे भारत 3.0 ट्रेन अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान है. यह ट्रेन 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 52 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि जापान यूरोप की बेहतरीन ट्रेनों को इसमें 54 सेकंड लगते हैं, उन्होंने कहा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वंदे भारत 3.0 की शोर और कंपन स्तर विश्व की अन्य ट्रेनों से कम है.

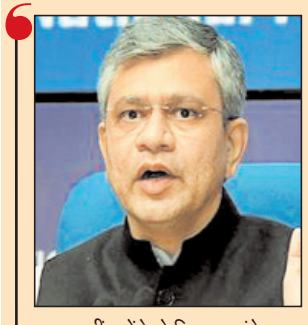

> रेल मंत्री ने कहा कि भारत में बढ़ती आबादी के चलते अब डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर बनाने का समय आ गया है. उन्होंने बताया कि 2047 तक 7,000 किलोमीटर लंबाई के कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जो विकसित भारत विज़न का हिस्सा हैं. वैष्णव ने निर्माताओं को गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा, 卐जो सुधार नहीं करेंगे, वे पिछड़ जाएंगे. खराब गुणवत्ता देने वाले आपूर्तिकर्ताओं को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के बारे में उन्होंने बताया कि 2,400 हॉर्सपावर की ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है. हम यह तकनीक आयात नहीं करेंगे, इसे खुद डिजाइन करेंगे,

धनतेरस से पहले सोने के दाम रिकॉर्ड पर, चांदी सुस्त

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर. धनतेरस और दिवाली से पहले भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की चमक चरम पर है. निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और वैश्विक अनिश्चितता के चलते 24 कैरेट गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बना लिया है, जबकि चांदी में हल्की नरमी बनी हुई है. त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले सोने की कीमतें नई ऊंचाई छू रही हैं.

24 कैरेट गोल्ड का भाव जीएसटी समेत 1,30,595 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है. वहीं, चांदी 1,81,761 प्रति किलो के भाव पर दर्ज की गई है. आईबीजेए (इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन) के अनुसार, 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 126,792 रुपये पर खुला, जबकि चांदी 1,633 रुपये सस्ती होकर 1,76,467 रुपये पर खुली. यह दर्शाता है कि चांदी की चमक सोने की तुलना में थोड़ी फीकी रही है. पिछले एक महीने में सोने की कीमत में करीब 11,443 की तेजी और चांदी में 35,666 का उछाल देखा गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपने स्वर्ण भंडार को 8.1प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है, जिससे बाजार में स्थायित्व आया है और निवेशकों का भरोसा बढ़ा है.

सेंसेक्स 174 अंक गिरा, निफ्टी भी फिसला

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर. सोमवार को शेयर बाजार ने दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद एक दिलचस्प मोड़ लिया. दोपहर 3 बजे तक तेजी से रिकवरी दिखाने के बावजूद, आखिरी 15 मिनट में तेज बिकवाली ने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को लाल निशान में बंद किया. निवेशकों की नजर अब निफ्टी के 25,200 के स्तर पर टिकी है, जो अगले कदम की दिशा तय करेगा. भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जबरदस्त हलचल देखने को मिली. दिनभर की गिरावट के बाद दोपहर 3 बजे बाजार में तेज रिकवरी देखने को मिली, लेकिन अंतिम 15 मिनट की बिकवाली ने सबकुछ बदल दिया. सेंसेक्स 174 अंक टूटकर 82,327 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 58 अंक फिसलकर 25,227 पर आ गया.

डिजिटल जोखिमों पर सतर्क रहने की जरूरत

आरबीआई डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने कहा- फिनटेक और डिजिटल मॉडल से नए प्रकार के जोखिम उभरे

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर. भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने कहा कि आंकड़ों पर अत्यधिक निर्भरता और कुछ चुनिंदा डिजिटल मंचों पर सेवाओं के केंद्रीकरण से उत्पन्न जोखिमों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये पूरे वित्तीय तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं.

'डिजिटल नवाचार के माध्यम से वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाना' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में स्वामीनाथन ने कहा कि डिजिटल नवोन्मेष अब केवल भुगतान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वित्तीय समावेशन को भी तेजी से बढ़ा रहा है.

उन्होंने कहा कि छोटी राशि के बीमा और पेंशन उत्पाद अब डिजिटल मंचों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे निम्न आय वर्ग के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिल रही है. उन्होंने कहा कि सीमा पार यूपीआई लिंक धन प्रेषण को तेज, सस्ता और सहज बना रहे हैं, जिससे औपचारिक चैनलों में लोगों का भरोसा बढ़ा है.

डिप्टी गवर्नर ने कहा कि फिनटेक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मिश्रित वित्तीय मॉडल (कर्ज, भुगतान, बीमा आदि) के तेजी से विस्तार ने जहां वित्तीय सेवाओं की सीमाओं को बढ़ाया है, वहीं नए प्रकार के जोखिम भी पैदा किए हैं.

> स्वामीनाथन ने कहा कि आरबीआई का लक्ष्य ऐसा माहौल बनाना है, जहां नवाचार जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ सके. उन्होंने बताया कि नियामक सैंडबॉक्स, नवोन्मेष केंद्र और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए सक्षम ढांचे जैसे कदमों के जरिये, रिजर्व बैंक सुरक्षित, टिकाऊ और ग्राहक-केंद्रित समाधानों को बढ़ावा दे रहा है.

एआई इकोसिस्टम से छोटे वित्तीय संस्थानों को भी मिलेगा फायदा

नेशनल एआई इकोसिस्टम से बड़े और छोटे संस्थानों को समान लाभ

एआई अब वित्तीय संस्थानों के लिए बोर्ड-स्तरीय गवर्नेंस मुद्दा बना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर. केंद्र सरकार के नेशनल एआई इकोसिस्टम निर्माण प्रयासों से अब वित्तीय सेवाओं में न सिर्फ बड़े, बल्कि छोटे प्लेयर्स को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संसाधनों की समान पहुंच मिलेगी. बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म ग्रांट थॉर्नटन भारत की बुधवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.

रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव का मतलब है कि कंपनियों को अपने सिस्टम को एआई प्लेटफॉर्म से जोड़कर डेटा सेट और मॉडल साझा करने होंगे. इसमें कहा गया है कि इंडिया एआई मिशन, एआई फंड, डीपीडीपी एक्ट और सीईआरटी-इन के साइबर सुरक्षा निर्देश मिलकर कंप्यूट, डेटा सुरक्षा और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को गति दे रहे हैं, जिन पर वित्तीय संस्थान अपनी डिजिटल विकास यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों और एनबीएफसी के लिए अब एआई एक बोर्ड-स्तरीय गवर्नेंस मुद्दा बन गया है. इसके लिए मॉडल जोखिम प्रबंधन और निष्पक्षता कार्यक्रम आवश्यक हैं. संस्थानों को एआई सिस्टम की सूची तैयार करने, पारदर्शिता बढ़ाने, निष्पक्षता कार्यक्रम विकसित करने और घटना रिपोर्टिंग को मौजूदा पर्यवेक्षी चैनलों से जोड़ने की सलाह दी गई है.

पारदर्शिता अपनाने की आवश्यकता

रिपोर्ट में जोर दिया गया कि एआई फंड और इंडिया एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म जैसी राष्ट्रीय पहलें छोटे संस्थानों की तकनीकी सीमाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. साथ ही, पूंजी बाजारों को एआई आधारित निर्णयों में भरोसा कायम रखने के लिए पारदर्शिता अपनाने की आवश्यकता बताई गई है. ग्रांट थॉर्नटन भारत ने कहा कि एआई अब प्रयोगात्मक उपकरण नहीं रहा, बल्कि यह एक विनियमित ढांचा बन चुका है, जिसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता और जिम्मेदार शासन जरूरी है.

यात्री वाहन बिक्री में 4.4 % की बढ़ोतरी

दोपहिया वाहनों की बिक्री में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर. सितंबर 2025 में वाहन उद्योग ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. खासकर यात्री, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में सकारात्मक रुझान देखने को मिला. विशेषज्ञ इसे त्योहारी मांग और हालिया जीएसटी बदलावों का परिणाम मान रहे हैं, जिन्होंने बाजार में नई ऊर्जा का संचार किया है.

देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में सितंबर 2025 का महीना बिक्री के लिहाज़ से सकारात्मक रहा. वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 4.4 प्रतिशत बढ़कर 3,72,458 इकाई पर पहुंच गई, जो कि सितंबर 2024 के आंकड़ों से अधिक है. यात्री वाहनों के साथ-साथ दोपहिया वाहनों की बिक्री में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह आंकड़ा 21,60,889 इकाई तक जा पहुंचा.

दालों में मंदी खाद्य तेलों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बुधवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये जबकि गेहूं में नरमी रही. दाल और चीनी के दाम भी फिसल गये. खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव देखा गया. विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का दिसंबर वायदा 13 रिंगिट चढ़कर 4,474 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया. अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 50.63 डॉलर के भाव बोला गया.

एयर इंडिया की 174 नई उड़ानों से यात्रियों को बड़ी राहत

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर. टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने आगामी विंटर शेड्यूल के तहत 174 नई उड़ानों की घोषणा की है. यह शेड्यूल 26 अक्टूबर 2025 से लागू होगा, जिसमें घरेलू और छोटी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का विस्तार शामिल है.

देश की प्रमुख विमानन कंपनी एयर इंडिया ने सर्दियों के मौसम में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी है. कंपनी ने 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले विंटर शेड्यूल में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कुल 174 नई उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है. यह कदम देश और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

समाचार विशेष

बिहार, यूपी पर कांग्रेस की नजर

अपने को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही

नई दिल्ली. कांग्रेस पार्टी ने अपनी दो सहयोगी पार्टियों को आशंकित कर दिया है. बिहार में सीट बंटवारे से लेकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में कांग्रेस ने जिस तरह की तिकड़में की हैं उससे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव आशंकित हुए हैं. उनको लग रहा है कि कांग्रेस उनके कंधे पर सवार होकर अपने को मजबूत करने का प्रयास कर रही है. इसका लंबे समय में राजद को नुकसान हो सकता है.

कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार के मुस्लिम महागठबंधन को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि कांग्रेस उसमें शामिल है. इसी तरह कांग्रेस ने दलित प्रदेश अध्यक्ष बना कर दलित व मुस्लिम गठबंधन पर ज्यादा ध्यान दिया है. ऊपर से राहुल गांधी की पहल पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की पार्टियों ने अत्यंत पिछड़ी जातियों यानी ईबीसी के लिए अलग से घोषणापत्र जारी किया. खुद राहुल गांधी इस मौके पर मौजूद थे. इसके अलावा कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर दलित और मुस्लिम उसके साथ लौटे तो अगड़ी जातियां, खास कर ब्राह्मण और भूमिहार स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ेंगे.

सवाल है कि कांग्रेस ने यह पहल अभी क्यों की है? उसका कारण यह है कि कांग्रेस को चिंता हो रही है कि कहीं सवर्ण मतदाताओं को प्रशांत किशोर ने अपने साथ जोड़ा और मुस्लिम व दलित उनकी ओर गए तो कांग्रेस के लिए स्पेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. दूसरे, लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस को लग रहा है कि संविधान व आरक्षण पर खतरा और वोट चोरी का आरोप अगर बिहार में काम कर गया तो बिहार में खोई हुई जमीन वापस हासिल होगी और अगले साल के चुनावों में कांग्रेस को फायदा होगा. जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार में तेजस्वी यादव यानी राजद को आशंकित किया उसी तरह उत्तर प्रदेश में उसने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को आशंकित कर दिया है.

> ध्यान रहे कांग्रेस ने यूपी को पूरी तरह से छोड़ दिया था. प्रियंका गांधी वाड्रा जब महासचिव थीं और यूपी की प्रभारी थीं तब थोड़ा बहुत काम हुआ लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया. लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के फिर से जीतने के बाद कांग्रेस में जान लौटी है. अब कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडेय ने कई कार्यक्रम तय किए हैं. कांग्रेस किसानों का एक सम्मेलन इसी महीने करने जा रही है. इसके अलावा पार्टी ने अभी से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. कांग्रेस पार्टी

टूट गया महागठबंधन?

लालू-तेजस्वी का ऑफर ठुकराकर ओवैसी-आजाद के साथ चली रालोजपा

पटना. पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कथित तौर पर बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल नहीं हो रही है. उनकी पार्टी अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी (एएसपी) के साथ गठबंधन करने की कोशिश करेगी.

सूत्रों का कहना है कि पटना में पारस के आवास पर हुई रालोजपा की बैठक में महागठबंधन में शामिल न होने का फैसला लिया गया. संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह, जिनके राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल होने की अटकलें हैं, भी बैठक में मौजूद थे. इस बात पर आखिरी मुहर समय ही लगाएगा.

सूत्रों के अनुसार, पारस ने पार्टी नेताओं को बताया कि रालोजपा को महागठबंधन में चार सीटों की पेशकश की गई थी, जो उनके लिए अपर्याप्त थीं. राजनीतिक गलियारों में ऐसी अफवाहें थीं कि लालू प्रसाद यादव ने पारस को राजद में विलय का प्रस्ताव दिया था. बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, या अगर हुई भी, तो इसका खुलासा नहीं किया गया. पारस ने बैठक में सभी को बताया कि ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टियां उनके संपर्क में हैं.

क्या थी पशुपति पारस की डिमांड

पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा, पारस अपने बेटे के लिए अलौली विधानसभा सीट से महागठबंधन का टिकट मांग रहे हैं, जहां से राजद के रामवृक्ष निवर्तमान विधायक हैं. यही कारण है कि पशुपति पारस और राजद के बीच बातचीत विफल रही है. इस खबर ने फिलहाल बिहार की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है. पशुपति पारस दिवंगत समाजवादी नेता रामविलास पासवान के भाई हैं. रामविलास के निधन के बाद, पारस ने पार्टी के छह में से पांच सांसदों के साथ मिलकर पार्टी तोड़ ली और केंद्रीय मंत्री बन गए. लोकसभा चुनाव से पहले, पारस को दरकिनार कर दिया गया और चिराग पासवान को वापस बुला लिया गया. तब से, पारस और उनकी पार्टी चुनावी मैदान से बाहर हैं.

केरल में एक करोड़ वोट कटने का डर

तिरुवनंतपुरम. बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध करने वाले संगठनों और बिहार की पार्टियों का कहना है कि उन्होंने विरोध किया, सड़क पर लड़े और कानूनी लड़ाई लड़ी इसलिए 69 लाख नाम कटे हैं अन्यथा डेढ़ करोड़ से ज्यादा नाम काटने की योजना थी.

पार्टियों का कहना है कि एसआईआर की घोषणा से पहले चुनाव आयोग से मुलाकात हुई थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि बिहार में 20 फीसदी वोट कटेगा. 20 फीसदी वोट का मतलब करीब एक करोड़ 60 लाख वोट है. उस समय मतदाता सूची में सात करोड़ 90 लाख मतदाता थे. इसी तरह का डर केरल में विपक्षी पार्टियों को सता रहा है.

केरल की विपक्षी पार्टियों यानी भाजपा विरोधी पार्टियों का कहना है कि अगर एसआईआर हुआ तो केरल में एक करोड़ नाम कट सकता है. ध्यान रहे वहां कुल तीन करोड़ के करीब मतदाता है. अगर इसमें से एक करोड़ नाम कटे तो इसका मतलब होगा कि एक तिहाई नाम कट जाएंगे. बिहार में कुल छह फीसदी नाम कटे हैं.

विशेष | **मांझी-कुशवाहा भी खुश कैसे?**

चिराग को क्यों मिली 29 सीटें

पटना. बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चा रविवार को आखिरकार समाप्त हो गई. रविवार को एनडीए के सभी घटक दल अंतिम सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत हो गए. जिसके बाद दलवार सीटों का ऐलान कर दिया गया है.

केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा की. प्रधान ने बताया कि एनडीए में भाजपा और जदयू दोनों को 101-101 सीटें मिली हैं.

इसका मतलब है कि जदयू और भाजपा एक बार फिर बिहार की राजनीति में बराबरी के स्तर पर चुनाव लड़ेंगे.

एनडीए ने अपने सहयोगियों के लिए एक नया फॉर्मूला अपनाया है. जिसके तहत एक सांसद के लिए छह विधानसभा सीटें दी गई हैं. लोक जनशक्ति पार्टी (रा) के चिराग पासवान को पांच सांसदों के लिए 29 सीटें मिली हैं. वहीं, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को प्रति सांसद छह सीटें और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को भी प्रति सांसद छह सीटें दी गई हैं. गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को पांच सीटें मिली थीं. जहां शत-प्रतिशत स्ट्राइक रेट दिखाते हुए उन्होंने जीत दर्ज की थी. इसके अलावा मांझी को लोकसभा चुनाव में एक सीट मिली थी उन्होंने भी उस पर जीत दर्ज की थी. कुशवाहा ने भी अपनी सीट पर जीत दर्ज की थी.

बड़ा दिल दिखाया 'बड़ा भाई' गया

2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की बजाय बराबर पर आ गई है. 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 सीटें जीती थीं. इस बार पार्टी ने अपनी संख्या 14 घटाकर 101 करने का फैसला किया है. जेडीयू ने यह कदम अपने सहयोगियों के लिए जगह छोड़ने और गठबंधन की एकता बनाए रखने के लिए उठाया है. 2020 के चुनाव में भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 78 सीटें जीती थीं. 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 10 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेगी.